

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठारीन अधिकारी प्रतिष्ठा पिलानिया आर ए एस
राजस्व अपील/225/रा.का.अधि./165/2022/जैसलमेर
अपीलांत

रेस्पोंडेंटगण

1. तारा पुत्र पनीया उर्फ पन्नाराम	1. नाथा पुत्र गुमना
2. दला पुत्र पनीया उर्फ पन्नाराम	2. भूरा पुत्र गुमना
3. शैरा पुत्र पनीया उर्फ पन्नाराम	3. नानजी पुत्र गुमना
4. गाला पुत्र पनीया उर्फ पन्नाराम जाति कोली निवासी सांवालासी तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर	4. कस्तुरा पुत्र खीया का.मु. 4/1नवीनाराम पुत्र कस्तुरा 4/2भारथाराम पुत्र कस्तुरा
	5. कस्तुरा पुत्र पनीया उर्फ पन्नाराम फौत के का.मु. 5/1नरसीराम पुत्र कस्तुरा 5/2हरचन्द पुत्र कस्तुरा 5/3शंकराराम पुत्र कस्तुरा 5/4रमेश पुत्र कस्तुरा 5/5कुम्पाराम पुत्र कस्तुरा 5/6नारणाराम पुत्र कस्तुरा 5/7प्रतापराम पुत्र कस्तुरा 5/8मीरोंदेवी पत्नी कस्तुरा जाति कोली निवासी सांवालासी तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर
	6. शाखा प्रबन्धक, एसबीबीजे सेड़वा
	7. तहसीलदार/उपपंजीयक, सेड़वा
	8. काकू पत्नी शंकराराम जाति मेघवाल निवासी कारटिया तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध सहायक कलक्टर सेड़वा द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 193/2018 बअनवान दला वगैरा बनाम नाथा वगैरा आदेश दिनांक 27.10.2022 के विरुद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री ठाकराराम चौधरी अपीलान्त की ओर से।
2. वकील श्री हसन खां रेस्पोंडेंट की ओर से।

निर्णय

दिनांक:- 20.06.2023

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि मौजा सांवालासी पटवार क्षेत्र तरला तहसील सेड़वा के खसरा संख्या 84 रकबा 18.18 बीघा, खसरा संख्या 101 रकबा 03.03 बीघा, खसरा संख्या 170/6 रकबा 17.03 बीघा, खसरा संख्या 181/02 रकबा 28.02 बीघा भूमि के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद मय आवेदन पेश कर निवदेन किया अपीलाधीन आराजी अपीलांतस/वादीगण की पैतृक खातेदारी की भूमि के विवाद को लेकर पेश किया, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा

Jainis
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

मौके एवं रेकर्ड यथास्थिति बनाये रखे तथा पत्रावली दिनांक 11.07.2018 को विप्रार्थीगण की तलवी हेतु नियत की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करते समय अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया, जिसके विरुद्ध हस्तगत अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट को जरिये सम्मन तलव किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलव की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

अपील में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए अपीलांटगण के अधिवक्ता ने बहस निवेदन किया कि अपीलाधीन आराजी रियासत काल में पक्षकारान के पूर्वज स्व. जवा ने अर्जित की जो विरासत में उसके दोनों पुत्रों खीमा व पनीया को प्राप्त हुई, दोनों भाई उक्त पैतृक जोत पर बहिस्ता बराबर काबिज हुए। बाड़मेर जिले का भू प्रबंध लगभग संवत् 2008-09 में प्रारम्भ होकर संवत् 2012-13 तक चला। मौजा सांवलासी के खेत खसरा संख्या 103 रकबा 0.05 बीघा गैर मुमकिन ढाणी, खसरा संख्या 104 रकबा 50.18 बीघा, खसरा संख्या 154 रकबा 02.13 बीघा कुल रकबा 53.16 बीघा कृषि भूमि की पैमाईश विप्रार्थीगण संख्या 01 व 03 के दादा स्व खीमा ने कराई जिसमें स्व. खीमा ने प्रार्थीगण के पिता को धोखे में रखकर सिर्फ अपने अकेले के नाम से खातेदारी दर्ज करवाई जबकि पैमाईश करते वक्त स्व. खीमा को चाहिये था कि वह इन दोनों खातों में स्वयं व प्रार्थीगण के वालिद पनीया का हिस्सा 1/2 दर्ज कराता परन्तु उसने ऐसा न कर मौजा सांवलासी के खेत खसरा संख्या 84 रकबा 18.18 बीघा, खसरा संख्या 101 रकबा 0.03 बीघा खसरा संख्या 170/6 रकबा 17.03 बीघा, खसरा संख्या 181/102 रकबा 28.02 बीघा अपना व प्रार्थीगण के पिता पनीया का नाम व मौजा सांवलासी के खेत खसरा संख्या 103 रकबा 05 बीघा, खसरा संख्या 104 रकबा 50.18 बीघा, खसरा संख्या 154 रकबा 02.13 बीघा अपना अकेले का नाम दर्ज करवा दिया व इस प्रकार स्व. खीमा ने अपने पक्ष में अधिक भूमि दर्ज करवा दी जिसका ज्ञान प्रार्थीगण के पूर्वज जो पूर्णतः अशिक्षित तथा वृद्ध तथा थे को नहीं हुआ प्रार्थीगण मौजूदा समय में दोनों खेतों के संयुक्त रकबा के हिस्सा 1/2 पर काबीज है जो वक्त बंदोबस्त से चला आ रहा है। यह दोनों खेत प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण के सामलाती है। भू प्रबंध विभाग ने इसे पृथक-पृथक खातेदारी में दर्ज कर अपने अधिकार क्षेत्र का दुरुपयोग किया है। वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की भूमि है तथा प्रार्थीगण का मौके पर अपने हिस्से की भूमि पर कब्जा काश्त चला आ रहा है एवं मौके पर रहवासी

Jain
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

ढाणियां, पशुवाडा आदि बने हुए है परन्तु वादग्रस्त आराजी का राजस्व रेकर्ड में नाम अंकित नहीं होने के कारण विप्रार्थीगण प्रार्थीगण को उसके हिस्से की भूमि से जबरन ताकत के बल पर वेदखल करना चाहते है तथा प्रार्थीगण को यह भी धमकियां कदे रहा है कि यदि वह प्रार्थीगण को उक्त भूमि से वेदखल करने से कामयाब नहीं हुए तो वह प्रार्थीगण की उक्त भूमि का वेचान अन्य किसी सरजोर व्यक्तियों को कर देंगे विप्रार्थीगण अपने इस नाजायज मकसद में कामयाब हो जाते है तो प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति भविष्य में करना संभव नहीं होगा। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मूल पत्रावली में अपीलांट के द्वारा प्रस्तुत आवेदन एवं संलग्न पेश दस्तावेजात के आधार पर प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन अपीलांटगण के पक्ष में है। मूल वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दस्तावेजात पर गौर किये बिना पारित किया गया। अतः अपीलांटगण की अपील स्वीकार फरमाई जावे।

वकील रेस्पोंडेंट ने बहस करते हुए बताया कि उतरदातागण रिक्ॉर्डेड खातेदार है जिनके विरुद्ध इंजेक्शन जारी किया जाना कतई न्यायोचित नहीं है। अपीलाधीन आराजी रेस्पोंडेंटस की स्वअर्जित संपत्ति है। अपीलाधीन आराजी पर हम रेस्पोंडेंटस का कब्जा काश्त है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करते वक्त विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पूर्णत पालन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। रिक्ॉर्डेड खातेदार के विरुद्ध स्थगन जारी किया जाता है तो रेस्पोंडेंटस को अपूर्णीय क्षति कारित होगी। मामला प्रथम दृष्टया एवं सुविधा का संतुलन भी रेस्पोंडेंटस के पक्ष में है। अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

पत्रावली का अवलोकन व विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गंभीरतापूर्वक अवलोकन नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। हस्तगत अपील अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के प्रार्थना-पत्र में पारित आदेश के विरुद्ध पेश की गई। मूल वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। उभयपक्षकारान के हकों का निर्धारण मूल वाद के निस्तारण पर ही संभव है। रेस्पोंडेंटगण द्वारा अपीलाधीन आदेश की आड़ में

Jaini
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाइमेर

अपीलांट के कब्जे काशत में हस्तक्षेप करते हैं तो अपीलांट के हितों पर कुठाराघात संभाव्य है। प्रथम दृष्टया मागला एवं सुविधा का संतुलन अपीलांट के पक्ष में प्रतीत होता है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांटगण की अपील स्वीकार करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांटस स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर सेडवा द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 193/2018 वअनवान दला वगै वनाम नाथा वगै. में में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.10.2022 को निरस्त किया जाता है तथा हाजा न्यायालय द्वारा हस्तगत अपील में पारित अंतरिम स्थग आदेश दिनांक 02.11.2022 को मूल वाद के निस्तारण तक कन्फर्म (पुष्ट) किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के लौटाया जावे।

Hans
(प्रतिष्ठा विभागाधीन अपील प्राधिकारी)
राजस्व अपील प्राधिकारी
वाड़मेर

यह निर्णय आज दिनांक 20.06.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Hans
राजस्व अपील प्राधिकारी
वाड़मेर